



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 1983/भाद्र 23, 1905

No. 156]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 1983/BHADRA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 40-ईटीसी (पीएन)/83

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1983

विषय :— 1-1-1984 से 31-12-1984 तक संयुक्त राज्य
अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य
राज्यों, कनाडा, आस्ट्रिया और फिनलैंड को खुले-
सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत सूत के कुछ कपड़ों
और/या ऊन और मनुष्य निर्मित धागों से तैयार
• मर्दों के निर्यात के लिए योजना।

सि० सं० 2/56/83-ई०-1—1. योजना :—यह योजना
1-1-84 से 31-12-84 तक की अवधि के लिए (1) संयुक्त
राज्य अमरीका यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों
(जर्मन गणराज्य, फ्रांस, इटली, यू० के०, आयरलैंड,
डेनमार्क और ग्रीस), आस्ट्रिया और कनाडा को सूत, ऊन और
मनुष्य निर्मित धागों और (2) फिनलैंड को सूत और मनुष्य
निर्मित धागों के कुछ कपड़े और/या तैयार मर्दों के निर्यात
में संबंधित है।

2. योजना के प्रशासन के लिए अधिकरण :—जब तक अन्यथा
रूप से निदेश न दिए जाएं सूती वस्त्र निर्यात संबंधित परिषद्
बम्बई (टेक्सप्रो सिल) सभी वस्त्रों और तैयार वस्तुओं के लिए
निर्यात हकदारी का आवंटन करेगी किंतु ऊनी वस्त्र और
तैयार वस्तुओं को छोड़कर जिनकी निर्यात हकदारी का आवं-
टन उन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संबंधित परिषद् (डब्ल्यू एंड
डब्ल्यू ई पी सी) द्वारा किया जाएगा। लेकिन सभी वस्त्र
और तैयार वस्तुएं जिनमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्तुएं भी
शामिल हैं के लिए आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संबंधित
परिषद् द्वारा किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र
उत्पादों की श्रेणियों की सूची सूती वस्त्र निर्यात संबंधित परिषद्
और उन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संबंधित परिषद् के पास
उपलब्ध है। सरकार को यह अधिकार होगा कि वह जैसा
उचित समझे, इस योजना के प्रशासन के लिए अधिकरणों के
संबंध में परिवर्तन कर सकती है।

3. मात्रा आवंटन की प्रक्रिया और आवंटन वर्ष का
विभाजन :—निर्यात के लिए मात्रा के आवंटन की तीन
पद्धतियां होंगी :—

30 प्रतिशत के वार्षिक स्तर का आवंटन भूतकाल के
निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। शेष (वार्षिक स्तर

का 70 प्रतिशत) भाग का आबंटन 'पहले आए सो पहले पाए' की संविदा आरक्षण के आधार पर और "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के आधार पर क्रमशः 55 : 45 के अनुपात में किया जाएगा। भूतकालीन निष्पादन के आधार पर आबंटन के अन्तर्गत 1-1-84 से 30-9-84 तक एक एकल अवधि होगी। लेकिन, (पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण और "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल) के लिए आबंटन वर्ष को छः छः महीनों की दो अवधियों में बांटा जाएगा जो 1-1-84 से 30-6-84 और 1-7-84 से 31-12-84 होगी। इन अवधियों "पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण और "पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल के अंतर्गत 60 प्रतिशत मात्रा पहले की आधी अवधि में और 40 प्रतिशत दूसरी अवधि में उपलब्ध होगा।

4. **खंडवार आरक्षण** :—जहां पर सूती, ऊनी और मनुष्य निर्मित धागे की निर्यात हकदारी मिश्रित की जाती है, ऊनी और संश्लिष्ट सामानों के लिए आरक्षण विशेष भावाओं की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। वस्त्र आयुक्त द्वारा वास्तविक मात्राओं का निश्चय गन वर्ष के पैटर्न और चालू वर्ष की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए क्रमशः परिषदों से पक्की जरूरतें प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित मात्रा की मांग की प्रवृत्ति को देखते हुए आणोधिनी किया जाएगा।

5. भूतकालीन निष्पादन हकदारी

5.1 **हकदारियों के निर्धारण के लिए अभिकरण** :—प्रत्येक निर्यातक के संबंध में भूतकालीन निष्पादन प्रक्रिया के अधीन कोर्ट की हकदारी की गणना करने वाला अभिकरण सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई (टेक्सप्रोसील) होगा। इस सम्बंध में वस्त्र आयुक्त प्रक्रिया निर्धारित करेंगे और कार्य का निरीक्षण करेंगे।

आधार अवधि

5.2 प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के लिए हकदारी का नियतन, प्रत्येक निर्यातक के लिए प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए 1981-82, और जनवरी-जून 1983 के दौरान औसत निर्यात के आधार पर किया जाएगा।

5.3 **भूतकालीन हकदारी का हस्तांतरण** :—निम्नलिखित शर्तों के आधार पर भूतकालीन हकदारी हस्तांतरणीय होगी :—

- (1) वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी निर्यातक को अपना हकदारी में किसी भी हिस्से का हस्तांतरण करने का एक निर्यातक को विकल्प होगा।
- (2) हस्तांतरित मात्रा उस हस्तांतरी के निर्यात के रूप में मानी जाएगी जो वास्तव में माल का लदान करता है।
- (3) हस्तांतरी के पास की हकदारी उन्हीं शर्तों एवं नियमों के अधीन होगी जो हस्तांतरक के पास के हकदारी के लिए लागू हैं।

(4) कोई निर्यातक, जिसमें अपनी मात्रा विशेष श्रेणी/देश के किसी अन्य निर्यातक को हस्तांतरित कर दी है वह उसी श्रेणी/देश के किसी अन्य निर्यातक से अपने लिए मात्रा के हस्तांतरण के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) विशेष देश/श्रेणी के भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तांतरण उस निर्यातक के लिए अनुमति नहीं होगा जिसके पास उसी देश/श्रेणी में "पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण कोटा है।

6. **"पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण पद्धति** :— "पहले आए सो पहले पाए" संविदा आरक्षण के आधार पर आबंटन के लिए निर्यातक को आवेदन पत्र के साथ जहां आबंटन की यूनिट किलोग्राम में होती हो वहां सभी श्रेणी/देशों के मामले में 50 पैसे प्रति दर्जन की दर पर, संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा की वस्त्र श्रेणियों में समतुल्य 5 पैसे/वर्ग गज की दर पर और यूरोपीय आदि सफुदाप नथ, संयुक्त राज्य अमरीका को रुमालों के निर्यातों के मामले में 12 पैसे प्रति दर्जन रुमाल की दर पर परिगणित मूल्य के लिए बैंक गारंटी द्वारा संभरित निष्पादन बांड देना होगा। अन्य संबंधित श्रेणियों देशों के लिए दर की घोषणा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा की जाएगी। इस पद्धति के अन्तर्गत पोतलदान विलों पर पृष्ठांकन 21 दिन की अवधि के लिए वैध होगा और इस शर्त के अधीन होगी कि संबंध अवधि समाप्त होने की तिथि से पूरे 10 दिनों से अधिक के लिए किसी भी अवधि के दौरान किया गया कोई भी पृष्ठांकन वैध होगा।

7. **"पहले आए सो पहले पाए" तैयार माल पद्धति** :— पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर मात्रा आबंटन के मामले में, निर्यातक को, जहां कहीं भी लागू हो, आवेदन पत्र और पोतलदान दस्तावेजों के साथ वस्त्र समिति का निरीक्षण पत्र, ए० आर० 4/ए० आर०-5 प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे। पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर आबंटन के भंडे लदान पृष्ठांकन की तारीख से पूरे 10 दिनों के भीतर करना पड़ेगा। लेकिन, वस्त्र आयुक्त के विशेष प्रमाणन के आधार पर वैध कारणों से कुछ विशेष मामलों में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

8. **घोसा रफ्तार की मर्दे** :—वर्ष 1983 के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार वस्त्र आयुक्त भूतकालीन निर्यातों और वर्तमान पद्धति के आधार पर घोसा रफ्तार वाली मर्दों का अभिज्ञान करेगा और उनकी सूची की घोषणा करेगा। ऐसी मर्दे निम्नलिखित रियायतों के लिए पात्र होगी :—

1. पेशगी धनराशि निक्षेप और बैंक गारंटी से संबन्धित प्रावधान उन मन्द गति वाली मर्दों के मामले में जो कि इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिज्ञान हैं, भूतकालीन निर्यातों और वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा असंग कर दी जाएगी।

2. मन्द गति वाली मदों की पहचान के लिए, आवेदक को बैंक गारंटी अथवा नकद निक्षेप के बिना वस्त्र संवर्धन समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में केवल निष्पादन बांड ही भेजना होगा।

9. पेशगी धनराशि का निक्षेप बैंक गारंटी और उनकी जम्मी. — जो निर्यातक पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण अथवा पहले आए सो पहले पाए तैयार मान के अन्तर्गत विशेष निर्यात हकदारी अथवा पूरे वर्ष भूतकालीन निष्पादन के अन्तर्गत उसे आबंटित हकदारी कोटे के 90 प्रतिशत तक निर्यात करता है तो उसे जुमाने का भुगतान नहीं करना होगा। जो निर्यातक 75 प्रतिशत तक किन्तु 90 प्रतिशत से कम निर्यात करता है, उसे भी अनुपात के हिसाब से जुमाना देना होगा। यदि निर्यात हकदारी का उपयोग 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यातक पूरे पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जम्मा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। जब भी ऐसा होगा, यह अनिवार्य बाध्यता के अधीन लागू होगी।

1.2 जिन मामलों में बाण्ड पर वैधाना अवधि के भीतर उपयोग 75 प्रतिशत तक हुआ है लेकिन 75% से कम नहीं और 90% से अधिक नहीं है, तो निर्यातक को समानुपातिक भुगतान करना होगा, यदि निर्यात हकदारी 75 प्रतिशत से कम है तो उसको निर्यात हकदारी वर्ष के दौरान अगली आबंटन अवधि के लिए वृद्धि की छूट दी जा सकती है। वृद्धि के लिए आवेदन पत्र सम्बद्ध अवधि के समाप्त होने से एक मास के भीतर भेज दी जाएगी। ऐसे मामलों में, निर्यातक को उपर्युक्त कंडिका 6 में दी गई दुगुनी दर से बैंक गारंटी के साथ एक बांड निष्पादन करना होगा। पूर्णतया निर्यात करने में असफल होने पर पूरी बाण्ड/बैंक गारंटी जम्मा की जा सकती है।

1.3 इस नीति के अनुसार जिन निर्यातकों को निर्यात का आबंटन किया गया है किन्तु जो उसका उपयोग नहीं करते हैं भविष्य में वे आबंटन के अयोग्य साबित होंगे और उन पर बिना किसी पक्षपात के उस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा सकती है।

10. पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जम्मा करने के विरुद्ध अपील :— आबंटित निर्यात हकदारी के उपयोग न करने के लिए पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी के जम्मा करने के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनो पर उपयुक्त विचार करने के लिए केवल निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी। सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी जम्मा किए जाने पर संबद्ध निर्यातक ऐसे जम्मीकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त, बंबई को उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र से शीघ्रनिर्णय देंगे। यदि किसी मामले में, निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र विभाग को दी जाएगी और उस पर सरकार द्वारा कायम की गई समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

11. निर्यात हकदारी आबंटन का पर्यवेक्षण : वस्त्र आयुक्त वस्त्र निर्यात हकदारी के आबंटन से सम्बन्धित मामलों पर दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण के अधिकार को जारी रखेगा। एक सम्बन्ध समिति, जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे और संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, वे समय-समय पर नीति के प्रचालन की पुनरीक्षा करेंगी। विचारों में विभिन्नता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

12. सीमाशुल्क द्वारा निकासी :—(क) नियंत्रण के अधीन उत्पाद : पोतलदान की अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तों पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए नियत किसी अन्य उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग भाग परेषणों के लिए मूल पोत परिवहन बिलों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

(ख) हथकरघा उत्पाद : जहां तक नियंत्रित मदों के संगत सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्त्रों के निर्यात का संबंध है, वहां सीमा शुल्क द्वारा पोतलदान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कंवीनेशन प्रपत्र के भाग-2 में, 'निरीक्षण पृष्ठांकन' के आधार पर दी जाएगी।

(ग) भारतीय मद के लिए क्रियाविधि : उन भारतीय मदों के बारे में जो कि ठेठ भारतीय परंपरागत लोक प्रचलित उत्पाद हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, यू.एस.ए., फिनलैंड आस्ट्रिया और कनाडा को निर्यात के लिए पोतलदान सीमाशुल्क, द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय या वस्त्र समिति द्वारा जारी किये गये उचित प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुमित किया जायगा।

13. (क) निर्यात प्रमाणपत्र, उद्गम प्रमाणपत्र और वीसा :— संगत द्विपक्षी समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाणपत्र सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् या उनके नाम में विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य परिषद् द्वारा जारी क्रिय जायेंगे :—

(1) यू०एस०ए० : (क) यू०एस० डालर 250 से अधिक मूल्य वाले परेषण की मिल निमित पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिये वीसा।

(ख) यू०एस० डालर 250 या इससे कम मूल्य के परेषण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिये छूट प्रमाणपत्र।

(2) ई०ई०सी० : (क) बुने हुए, पावरलूम और मिल-निमित मूल की पोशाकों, जो नियंत्रण के अधीन हैं के लिये निर्यात प्रमाणपत्र और उद्गम प्रमाणपत्र।

(3) कनाडा : बुने हुए, पावरलूम और मिल-निमित मूल की पोशाकों, जो

नियंत्रण के अधीन है, केवल 500 या इससे कम कनेडियन डालर मूल्य के परेषण के लिये निर्यात प्रमाणपत्र।

- (4) आस्ट्रिया : नियंत्रण या निगरानी की शर्त के अधीन सूती पावरलूम/मिल निर्मित पोशाकों के लिये निर्यात प्रमाणपत्र।

13(ख) : हथकरघा छूट प्रमाणपत्र :—नियंत्रित मर्दों से संगत सभी हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं के कनाडा को निर्यात, सूती वस्त्र, हथकरघा वस्त्रों/तैयार वस्तुओं का आस्ट्रिया को निर्यात, सभी हथकरघा वस्त्र और तैयार वस्तुओं का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के राज्यों तथा यू.एस.ए. को निर्यात के मामले में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिये द्विपक्षीय समझौते में यथानिर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगा।

14. निर्यात भारत के सभी पत्तनों से अनुमित किया जायेगा।

15. पूर्व मचना दिये बिना पहले के किसी भी उपलब्ध का संशोधन करने के लिये सरकार को अधिकार है।

16. संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय के पते निम्नलिखित अनुसार हैं :—

1. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, इंजीनियरिंग सेक्टर, पांचवी मंजिल, 9, मैथ्यु रोड, बंबई-400004
2. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, 612/714, अशोका इस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, न दिल्ली-110001.
3. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, पोस्ट बॉक्स नं 11500, बंबई-400 020:
4. वस्त्र समिति, "क्रिस्टल", 79, डा० एनी बेमेट रोड, बंबई-400 018.
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वेस्ट ब्लॉक-7, आर० के० परम, नई दिल्ली-110022.

आनंद स्वरूप, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 40-ETC(PN)/83

New Delhi, the 14th September, 1983

Sub. :—Scheme of Exports under OGL-3 of certain Fabrics and/or made-up items made from Cotton, Wool and Man-made

Fibres, to USA, European Economic Community Member States, Canada, Austria and Finland from 1-1-1984 to 31-12-1984.

F. No. 2/56/83-E.I.—1. The Scheme.—This Scheme relates to the exports of certain Fabrics and/or made-ups items of (i) Cotton, Wool and Man-made fibres to USA, European Economic Community Member States, (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, U.K., Ireland, Denmark and Greece) Austria and Canada and (ii) Cotton and Man-made fibres to Finland for the period 1-1-1984 to 31-12-1984.

2. Agencies for the Administration of the Scheme.—Unless otherwise directed, the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay (TEX-PROCIL) will allocate export entitlements for all fabrics and made-ups except woollen fabrics and made-ups for which Export entitlement allocation will be done by the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi (W&WEPC). However, necessary certification for all fabrics and made-ups including the woollen fabrics and made-ups will be done by the Cotton Textiles Export Promotion Council. Lists of categories of textiles products covered under the scheme are available with the Cotton Textiles Export Promotion Council and the Wool and Woollen Export Promotion Council. Government reserves the right to make changes as considered appropriate, with regard to the agencies for the administration of the Scheme.

3. Systems and Quantum of Allotment, and Divisions of the Allotment year.—There will be three systems of allocation of quantity for export :—

3.1 30% of the annual level will be allocated on the basis of past performance. The balance (70% of Annual level) will be allocable on FCFS contract reservation basis and FCFS ready goods basis in the ratio of 55 : 45 respectively. For the purpose of allotment on the basis of past performance there will be a single period from 1-1-1984 to 30-9-1984. However, for FCFS contract reservations and FCFS ready goods, the year will be divided into two six months period 1-1-1984 to 30-6-1984 and 1-7-1984 to 31-12-1984.

60% of the quantity available under these systems (FCFS Contract reservation and FCFS Ready Goods) will be allotted during the first period and 40% during the second period. The above periods/systemwise ratios may, however, be modified by the Government depending upon the demand patterns and other parameters.

4. Reservation for Segments.—Wherever export entitlements for cotton, woollen and man-made fibres are combined, the reservation for woollen and synthetic items will be done in terms of specific quantities. The actual quantities will be deter-

mined by the Textile Commissioner after ascertaining the firm requirements from the respective Councils, keeping in view the past pattern, and prevailing trends. Depending upon the demand trend, the quantities so fixed may be modified.

5. Past performance entitlement.—(1) Agency for determining entitlements.—The agency for calculation of the entitlement under the past performance system in respect of each exporter will be the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, (TEXPROCIL). The Textile Commissioner, will lay down procedures in this regard and supervise the work of the TEXPROCIL.

(ii) Base Period.—The entitlement shall be determined prorata for each country/category combination on the basis of the average of export during 1981-1982 and January-June 1983 for each country/category for each exporter.

(iii) Transferability of past performance entitlement.—PP entitlement shall be transferable subject to the following conditions :—

- (a) An exporter will have the option to transfer any portion of his entitlement to any other exporter at any time during the year.
- (b) The quantity transferred shall be counted as exports of the transferee, who actually ships the goods.
- (c) The entitlement in the hands of the transferee shall be subject to the same terms and conditions as those applicable to it in the hands of the transferer.
- (d) Any exporter, who has transferred quantities in a particular category/country to another exporter shall not be eligible to seek transfer from any other exporter to himself in the same category/country.
- (e) Transfer of PP entitlement in a particular country/category shall not be allowed to the exporters who have FCFS contract reservation quota in the same category/country.

6. FCFS contract reservation systems.—For allotment on FCFS contract reservation basis, the exporters will have to submit, alongwith the application, performance bond backed by bank guarantee for the value calculated at the rate of 50 paise/per dozen. In case of all categories/countries where the unit of allocation is in Kilogram, 5 paise per square yard equivalent in Fabric categories of USA and Canada and 12 paise per dozen in case of exports of handkerchiefs to European Economic Countries and USA. The rates for other categories/Countries concerned will be announced by TEXPROCIL under this system, endorsement by the TEXPROCIL shall be valid for a period of 21 days subject to the condition that no endorsement made during any period shall be valid beyond

10. clear days from the expiry of the period concerned.

7. FCFS Ready goods system.—In the case of allocation of quantity on the basis of FCFS ready goods, the exporters will have to submit the Textile Committee inspection certificate, AR 4/AR 5 forms, whenever applicable alongwith the application and shipping documents. Shipments against allocation of FCFS ready goods basis will have to be offered within 10 clear days from the date of certification. However, this period can be extended in exception cases for valid reasons on specific authorisation from Textile Commissioner.

8. Slow moving items.—In line with practice followed during the year 1983, the Textile Commissioner, will identify and announce a list of slow moving items on the basis of past exports and prevailing trends. Such items will be eligible for the following relaxations :—

- (i) The provisions regarding earnest money deposits and bank guarantee would be dispensed with in the Case of slow-moving items, specially identified for this purpose, by the Textile Commissioner on the basis of past exports and prevailing trends.
- (ii) For the identified slow-moving items, applicants will have to submit only the performance bond in the proforma prescribed by TEXPROCIL without any Bank Guarantee or Cash deposit.

9. Earnest money deposits, Bank guarantees and forfeitures thereof.—An exporter who exports not less than 90% of the export entitlement allotted to him under FCFS Contract Reservation or FCFS ready goods system in a particular export entitlement period of within the whole year under Past Performance System, will not be liable to the forfeiture of EMD/Bank Guarantee. An exporter who performs not less than 75% but less than 90% will have to pay proportional forfeiture. If the export entitlement utilisations less than 75% the exporter will be liable to forfeiture of his EMD/Bank Guarantee in full. This will be subject to force majeure conditions, wherever these arise.

9.2 In cases where the utilisation is not less than 75% within the validity period, but less than 75% to 90% exporter will have to pay proportional forfeiture. If the export entitlement is less than 75% he may be given the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Application for extension shall be filed within one month of the end of the relevant period. In such cases, the exporter will have to execute a bond supported by Bank Guarantees at double the rates as given in para 6 above. In the case of his failure to export fully, the bond/bank guarantee will be liable to be forfeited in full.

9.3 Exporters to whom export entitlements are allotted in terms of this policy but who do not utilise them would render themselves liable to disqualification from future allotment, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

10. Appeal against forfeiture of EMDs/Bank Guarantees.—For the purpose of giving due consideration to representations made by exporters against forfeiture of EMDs/Bank Guarantees for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMDs/Bank Guarantees by the Cotton Textiles Export Promotion Council the exporters concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the Communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. If, in any case, the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will lie with Department of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by the Government.

11. Supervision of allocation of export entitlements.—The Textile Commissioner, Bombay, will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A Coordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCs as members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

12. Clearance by Customs.—A. Products under restraint.—Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement of the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

B. Handloom products.—In so far as exports of all handlooms fabrics/made-ups corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textile Committee in part-2 of the Combination Form.

C. Made-ups falling under India items.—In respect of 'India Items' which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria and Canada on the basis of appropriate certificate issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) or the Textile Committee.

13. (A) Export certificate, certificate of origin and Visa.—The following certification required

under the relevant Bilateral Textile Agreement will be issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council or any other body duly authorised in this behalf :—

- | | | |
|--------------|---|---|
| (i) U.S.A. | : | (a) Visa for all Mill-made fabrics and made-ups consignments valued over US \$250.
(b) Exempt certificate for consignments valued at US \$250 or less. |
| (ii) EEC | : | Export Certificate and Certificate of origin for all restrained items of Powerloom/Mill-made/Knitted origin. |
| (iii) Canada | : | Export Certificates for fabrics and made-ups of powerloom, mill-made or knitted origin which are subject to restraint except for consignments valued at less than Canadian \$500. |
| (iv) Austria | : | Export Certificates for Fabrics/made-ups of powerloom/mill-made origin subject to restraint of surveillance. |

13. (B) Handloom exempt certificate.—In the case of export of all Handloom fabrics/Made-ups corresponding to restrained items to Canada, Cotton Handloom Textile Fabrics/Made-ups to Austria, all handloom fabrics and made-ups to EEC and the U.S.A. the Textiles Committee will issue the Certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

14. Exports will be allowed from any port in India.

15. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

16. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and of the Offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. The Cotton Textiles Export Promotion Council,
Engineering Centre, 5th Floor,
9, Mathew Road,
Bombay-400004.
2. The Wool and Woollens Export Promotion Council,
612/714, Ashoka Estate, 24. Barakhamba Road,
New Delhi-110001.
3. Office of the Textile Commissioner,
Post Box No. 11500,
Bombay-400020.
4. Textiles Committee,
'Crystal'
79, Dr. Annie Besant Road,
Bombay-400018.
5. Development Commissioner (Handicrafts),
West Block VII,
R. K. Puram,
New Delhi-110022.

Sd/-
ANAND SARUP, Addl. Secy.